करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

अप्रैल (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- उत्तर प्रदेश में बेसहारा गोवंश के लिये सफारी निर्माण 3
- स्कूल चलो अभियान 3
- उत्तर प्रदेश की 60 नदियों के पुनरुद्धार का खाका तैयार 4
- अयोध्या एयरपोर्ट 4
- उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल 4
- गीतांजलिश्री की कृति 'रेत समाधि' 5
- राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड-1 में उत्तर प्रदेश 5
- उत्तर प्रदेश विधानपरिषद चुनाव, 2022 5
- अग्नि सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ 6
- दस्तक अभियान 6
- मथुरा में प्रत्येक तीर्थस्थल पर बनेंगे पर्यटक सुविधा केंद्र 7
- वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड समारोह में 4 श्रेणियों में मिले पुरस्कार 7
- लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को कैबिनेट की मंज़ूरी 7
- मनरेगा के तहत 150 नर्सरी विकसित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार 8
- उत्तर प्रदेश में पुलिस सुधार की कवायद 8
- उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट पॉलिसी, 2022 9
- उत्तर प्रदेश सरकार का त्वरित न्याय की दिशा में प्रयास 9
- ऑपरेशन कायाकल्प 9
- कायाकल्प योजना 10
- नीति आयोग की नवोन्वेषी कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला 10
- उत्तर प्रदेश के सभी थानों में स्थापित किये जाएँगे साइबर हेल्पडेस्क 11
- उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में लॉन्च होगा सामुदायिक रेडियो स्टेशन 11
- चेक डैम्स और तालाबों से बदल रही सूखाग्रस्त बुंदेलखंड की तस्वीर 12
- वाराणसी में बनेगा उत्तर प्रदेश का अपना 'सिल्क एक्सचेंज' 12

दृष्टि The Vision

नोट :

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में बेसहारा गोवंश के लिये सफारी निर्माण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव ने बेसहारा गोवंश को सहारा देने के लिये प्रदेश भर में गोसफारी बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत प्रदेश भर के वन क्षेत्र की ज़मीन पर बाड़ बनाकर शेडयुक्त आश्रय निर्माण किया जाएगा, जहाँ गोवंश के लिये चारा एवं पानी की भी व्यवस्था होगी।
- गोवंश संरक्षण के लिये गोसफारी निर्माण पर सहमति 14 मार्च को पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग द्वारा आयोजित बैठक में बनीं थी, जिसमें प्रदेश भर के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, वेटनरी यूनिवर्सिटी के डीन, गोशाला संचालक एवं एनजीओ पदाधिकारी शामिल हुए थे।
- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में गोवंश के संरक्षण हेतु गोशाला निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश गोशाला योजना' का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार द्वारा गोशाला खोलने पर अनुदान प्रदान किया जाता है, जो कि प्रति गाय 30 रुपए है।

स्कूल चलो अभियान

चर्चा में क्यों?

4 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले ज़िले श्रावस्ती में महीने भर चलने वाले 'स्कूल चलो अभियान' की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- इसका उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना है।
- इस अभियान के तहत कम साक्षरता दर वाले ज़िलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूँ और रामपुर शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री ने विधायकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से एक-एक स्कूल अपनाने और अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालयों, स्मार्ट कक्षाओं, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, शौचालय आदि जैसी सुविधाओं के संदर्भ में स्कूलों के परिवर्तन की दिशा में काम करने का भी निर्देश दिया।
- गौरतलब है कि 2017 में ऑपरेशन कायाकल्प के शुभारंभ के बाद से 1.34 लाख प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा, फर्नीचर, शौचालयों के निर्माण, स्मार्ट क्लास को शामिल करने और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में सुधार के प्रावधान के साथ उत्तर प्रदेश में स्कूलों को नया रूप दिया गया है।

उत्तर प्रदेश की 60 नदियों के पुनरुद्धार का खाका तैयार

चर्चा में क्यों ?

5 अप्रैल, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई शासनस्तरीय बैठक में प्रदेश की 60 नदियों के पुनरुद्धार का खाका तैयार कर लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- नदी पुनरुद्धार के इस कार्य में आईआईटी बीएचयू, कानपुर और रुड़की का तकनीकी सहयोग लिया जाएगा।
- नदियों के पुनरुद्धार और संरक्षण संबंधी इस पहल में वरुणा, गोमती, बाणगंगा, नंद, कर्मनाशा तथा गड़ई सहित 60 नदियों को शामिल किया जाएगा।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण निवारण और नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जून 2014 में 'नमामि गंगे' नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया था।
- इस कार्यक्रम के तहत 152 सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से पूर्ण हो चुकीं 46 परियोजनाओं ने 632 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता सृजित की है। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत 28 रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, 182 घाटों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा 118 श्मशान का निर्माण भी किया गया है, जिससे गंगा नदी के पर्यावरणीय स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

अयोध्या एयरपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि अयोध्या एयरपोर्ट प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और जेवर के बाद पाँचवा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा।
- अयोध्या एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम वर्ष 2021 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, जबकि 10 नए एयरपोर्टों के विकास पर काम चल रहा है।
- उपरोक्त एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में वायु संपर्क का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) की छठी बटालियन स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यूपीएसएसएफ का गठन सितंबर 2020 में प्रदेश के कोर्ट, प्रमुख धार्मिक स्थलों एवं प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिये किया गया था।
- परिणामस्वरूप जून 2021 में यूपीएसएसएफ की पाँच बटालियन गठित की गई थीं, जिनमें लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा व सहारनपुर की बटालियन शामिल हैं। यूपीएसएसएफ की प्रथम बटालियन लखनऊ में मेट्रो की सुरक्षा में तैनात है।
- सरकार द्वारा इन सभी बटालियन की स्थापना के लिये पीएसी कमांडेंट को यूपीएसएसएफ के कमांडेंट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
- अयोध्या में छठी वाहिनी का गठन उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली-2021 के तहत किया गया है।

नोट :

गीतांजलिश्री की कृति 'रेत समाधि'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश की गीतांजलिश्री के उपन्यास 'रेत समाधि' के अंग्रेज़ी अनुवाद 'टॉम्ब ऑफ सैंड' (Tomb of Sand) को बुकर पुरस्कार के शीर्ष छह दावेदारों में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- 'टॉम्ब ऑफ सैंड' हिन्दी की पहली रचना है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर परुस्कार के शीर्ष छह दावेदारों में शामिल किया गया है।
- 'रेत समाधि' का 'Tomb of Sand' नामक अंग्रेज़ी अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया है।
- 'रेत समाधि' गीतांजलिश्री का पाँचवा उपन्यास है।
- गौरतलब है कि गीतांजलिश्री का जन्म 1957 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था।

राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड-1 में उत्तर प्रदेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड-1 से संबंधित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक 13वीं, जबकि स्कोर 41.0 है।
- यह सूचकांक 2019-20 के आँकड़ों के आधार पर नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है।
- गौरतलब है कि यह सूचकांक 6 मानकों- डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय स्थिरता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, नई पहल तथा पहुँच, वहनीयता एवं विश्वसनीयता के आधार पर जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किये गए प्रयासों को ट्रैक करता है।
- विभिन्न मानकों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्कोर निम्न प्रकार है-
- डिस्कॉम का प्रदर्शन- 59.9
- ऊर्जा दक्षता- 42
- पहुँच, वहनीयता एवं विश्वसनीयता- 37.8
- पर्यावरणीय स्थिरता- 30.9
- स्वच्छ ऊर्जा पहल- 12.6
- नई पहल- 27.4

उत्तर प्रदेश विधानपरिषद चुनाव, 2022

चर्चा में क्यों?

12 अप्रैल, 2022 को उत्तर प्रदेश विधानपरिषद की 36 सीटों के लिये हुए चुनावों के नतीजे घोषित किये गए।

प्रमुख बिंदु

- 36 सीटों के इन चुनावों में 33 सीटें भाजपा, 1 सीट जनसत्ता दल लोकतंत्रिक तथा 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को प्राप्त हुई हैं।
- उत्तर प्रदेश विधानपरिषद में प्रमुख राजनीतिक दलों की संख्या/स्थिति निम्न प्रकार है-

नोट :

- भारतीय जनता पार्टी- 66
- समाजवादी पार्टी- 17
- बसपा- 4
- हाल ही में संपन्न हुए इन चुनावों का संबंध स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से है। गौरतलब है कि विधानपरिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों, जैसे- नगरपालिका और ज़िला बोर्डों आदि द्वारा किया जाता है।

अग्नि सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

14 अप्रैल, 2022 को ग्रीष्मकाल के दौरान आग की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई।

प्रमुख बिंदु

- सुरक्षा सप्ताह में इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया कि 'रोकथाम इलाज से बेहतर है', ताकि आग से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सके।
- 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाए जाने वाले अग्नि सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ को चिह्नित करने के लिये अग्निशमन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास पर फ्लैग पिन भी लगाया गया है।
- अग्नि सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य न केवल राज्य को आग के खतरों से बचाना है, बल्कि जनता के बीच सावधानी और जागरूकता पैदा करना भी है, इसमें विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों, खेत-खलिहान और कच्चे घरों को आग के खतरों से बचाना शामिल है।
- अग्नि सुरक्षा सप्ताह का मूलमंत्र औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में 'अग्नि सुरक्षा सीखें, उत्पादकता बढ़ाएँ' है।
- इस अभियान में लोगों को डिजिटल माध्यम से आग लगने की मुख्य वजहों, जैसे- बिजली का शार्ट-सर्किट, बिजली की ओवरलोडिंग, गैस सिलेंडरों का लापरवाही से इस्तेमाल, धूम्रपान आदि के बारे में जागरूक करने के साथ आपातकालीन स्थिति में मॉक ड्रिल द्वारा सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा।

दस्तक अभियान

चर्चा में क्यों ?

15 अप्रैल, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जलजनित और वेक्टरजनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिये दस्तक अभियान शुरू किया।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश के लोगों को इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोगों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा।
- इस अभियान के तहत आशा व आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को जलजनित एवं मच्छरजनित विभिन्न बीमारियों से लोगों को अवगत कराने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, जिसने देश में निगरानी समितियों की अधिकतम संख्या (60,000 से अधिक) का गठन किया है, मौसमी बुखार, मच्छर और पानी से होने वाली बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- इसके अतिरिक्त वेक्टरजनित रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये एक संचारी रोग नियंत्रण अभियान के साथ-साथ साप्ताहिक मुख्यमंत्री जन-आरोग्य मेला पहले ही शुरू किया जा चुका है।

मथुरा में प्रत्येक तीर्थस्थल पर बनेंगे पर्यटक सुविधा केंद्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेंटर (पर्यटक सुविधा केंद्र) बनाने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- योजना के तहत सभी सेंटर एक-एक हेक्टेयर भूमि पर बनाए जाएंगे।
- गौरतलब है कि मथुरा में अब तक श्रीकृष्ण जन्म-स्थान क्षेत्र के 10 वर्ग किमी. के दायरे में आठ तीर्थस्थल घोषित किये जा चुके हैं।
- वृंदावन में पर्यटक सुविधा केंद्र पहले से ही उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध हैं-
- 55 बसों की पार्किंग सुविधा
- चार हॉल में 100-100 बेड की व्यवस्था
- श्रद्धालुओं के लिये खुद की रसोई की सुविधा, कैंटीन आदि।

वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड समारोह में 4 श्रेणियों में मिले पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

18 अप्रैल, 2022 को गुजरात के सूरत में भारत सरकार के शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में वाराणसी स्मार्ट सिटी को चार अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- वाराणसी को जिन 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार है-
- 'कोविड इनोवेशन अवार्ड'
- 'स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड'
- 'सिटी अवार्ड'
- 'जल संरक्षण अवार्ड'
- कोविड-19 महामारी के प्रकोप और सख्त लॉकडाउन के दौरान उल्लेखनीय पहल के लिये कोविड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। इस अवधि के दौरान काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने 'एकीकृत वार रूम' के रूप में कार्य करते हुए ज़िला प्रशासन, आपातकालीन सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग, टेलीमेडिसिन तथा नगर निगम आदि से संबंधित सुविधाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप में उपलब्ध कराया।
- इसी प्रकार शहर को इसके कुशल कामकाज और परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिये 'स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड' से सम्मानित किया गया है।

लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को कैबिनेट की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

19 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- लखनऊ का यह केंद्र देश भर में स्थापित होने वाले कुल छह केंद्रों में से एक है।

नोट :

- डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि इसके लिये लखनऊ के सरोजिनी नगर के जैतीखेड़ा में एनसीडीसी को 2.5 एकड़ ज़मीन 30 साल के लिये लीज़ पर दी गई है।
- इसके अतिरिक्त कैबिनेट बैठक में कुछ अन्य निर्णय भी लिये गए, जिनका विवरण निम्न प्रकार है-
- राज्य सरकार ने हरिद्वार के अलकनंदा गेस्ट हाउस में 3000 वर्ग मीटर में बने भागीरथी गेस्ट हाउस को उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव भी मंज़ूरी दे दी है।
- निजी क्षेत्र के सहयोग से आगरा, मथुरा और प्रयागराज में हेलीपोर्ट विकसित किये जाएंगे। साथ ही पर्यटन विभाग को भी लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान के पास एक हेलीपैड मिलेगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी न्यायिक सेवा नियमावली में विकलांगों के लिये निर्धारित 4% आरक्षण कोटा की अनुमति के साथ ही आयुर्वेद संस्थान के लिये भूमि के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई।

मनरेगा के तहत 150 नर्सरी विकसित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि किसान केंद्रित पहल के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 150 नर्सरी विकसित करेगी।

प्रमुख बिंदु

- इस निर्णय के अनुरूप ग्रामीण विकास विभाग को 100 दिन में नर्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।
- इन नर्सरी में 22.50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और प्रत्येक नर्सरी में कम-से-कम 15 लाख पौधे होंगे, जिनमें पारंपरिक फसलों के साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाले फूल, फल और सब्जियाँ शामिल होंगी।
- प्रत्येक ज़िले में अधिकतम दो नर्सरी स्थापित की जाएंगी। इनमें किसानों को सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, कालमेघ, कौंच, शतावरी, तुलसी, एलोवेरा जैसे औषधीय पौधों की खेती के साथ-साथ अन्य फूलों और फलों की खेती के तरीकों से अवगत कराया जाएगा।
- यह कदम राज्य में हरित आवरण में वृद्धि के साथ पर्यावरण को लाभ पहुँचाएगा और लोगों को वृक्षारोपण के लिये प्रोत्साहित करेगा।

उत्तर प्रदेश में पुलिस सुधार की कवायद

चर्चा में क्यों?

21 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में पुलिस सुधार से संबंधित कई दिशा-निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ते) की दक्षता बढ़ाने के लिये इसके अधिकारियों एवं जवानों को अमेरिका की संघीय जाँच एजेंसी (FBI) एवं होम लैंड सिक्योरिटी जैसी एजेंसियों से प्रशिक्षण दिलवाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है।
- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कुछ अन्य निर्देश भी दिये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है-
- सीबीआई की तर्ज़ पर यूपी स्पेशल पुलिस एस्टेबिलिशमेंट का गठन।
- एटीएस की स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम (स्पॉट) की नई टीम के लिये अगले 100 दिनों में जवानों का चयन कर प्रशिक्षण दिलाना।
- अगले 100 दिनों में अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स की इकाई का गठन किया जाना।
- पुलिस बलों में लैंगिक समानता से संबंधित भी कुछ निर्णय लिये गए हैं, जैसे-
- महिलाकर्मियों की संख्या दोगुना किया जाना।
- धार्मिक स्थलों के पास पिंक बूथ का निर्माण।
- हर महिला बीट सिपाही को स्कूटी उपलब्ध कराना।
- महिला कमांडो टीम का गठन।

नोट :

उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट पॉलिसी, 2022

चर्चा में क्यों ?

21 अप्रैल, 2022 को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (हथकरघा एवं कपड़ा) डॉ. नवनीत सहगल की अध्यक्षता में टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट पॉलिसी, 2022 के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिये बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने के साथ ही हथकरघा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करना है।
- इसके अंतर्गत उद्यमियों को 40% तक की पूँजी निवेश सब्सिडी के साथ ही विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ मुहैया कराने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही प्रस्तावित नीति में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के निवेशकों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
- नई नीति में शत-प्रतिशत स्टांप शुल्क एवं भूमि लागत अनुदान देने का प्रावधान किया जा रहा है।
- राज्य से निर्यात बढ़ाने के लिये निर्यात सब्सिडी और बिजली शुल्क में छूट भी दी जाएगी, साथ ही निजी टेक्सटाइल पार्क विकसित करने वाले विकासकर्ताओं को 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
- गौरतलब है कि कपड़ा और परिधान नीति, 2017 के तहत हथकरघा और कपड़ा क्षेत्र में निवेश के 79 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 53 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिये और 26 बड़े, मेगा और सुपर मेगा उद्योगों के लिये थे।

उत्तर प्रदेश सरकार का त्वरित न्याय की दिशा में प्रयास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने पिछले वर्षों में हुई कार्रवाई को आधार बनाते हुए प्रभावी पैरवी की कार्ययोजना तैयार की है।

प्रमुख बिंदु

- छह माह की इस कार्ययोजना में मृत्युदंड की सज़ा वाले अपराधों में अभियुक्तों और उम्रकैद की सज़ा वाले 300 अभियुक्तों को जेल भिजवाने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसी प्रकार पॉक्सो एक्ट के तहत तेज़ी से पैरवी कर 10 प्रकरणों में आरोपित को 1 माह के भीतर सज़ा दिलाई जाएगी।
- इसी प्रकार गृह विभाग द्वारा एक-दो वर्षीय कार्ययोजना का भी निर्माण किया गया है।
- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का 2019 में महिलाओं के प्रति अपराधों में सज़ा दिलाने का प्रतिशत 55.2 था, जो 2020 में बढ़कर 61 हो गया।
- महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ही प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी। साथ ही उत्तर प्रदेश डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई-प्रासीक्यूशन पोर्टल पर सूचनाएँ दर्ज कराने के मामले में भी सबसे आगे है।

ऑपरेशन कायाकल्प

चर्चा में क्यों ?

25 अप्रैल, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य द्वारा संचालित स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत पारंपरिक शिक्षण पद्धति के साथ तकनीक आधारित शिक्षा का प्रयोग किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं में लगातार सुधार लाने के उद्देश्य से 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को 'स्मार्ट स्कूलों' में बदला जाएगा।

नोट :

- इसके तहत लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालय स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदानों, उचित शौचालयों, पुस्तकालयों, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, कला कक्षों और अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किये जाएंगे।
- इसी संदर्भ में सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकल्प को पूरा करने और सरकारी स्कूलों को सुविधाओं एवं बुनियादी ढाँचे के मामले में निजी स्कूलों के बराबर बनाने के लिये एक कार्य योजना तैयार की गई है।
- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'ऑपरेशन कायाकल्प' की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी।

कायाकल्प योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क मार्ग परिवहन निगम (UPSRTC) द्वारा 'कायाकल्प योजना' के तहत सभी मंडल के लिये नोडल अधिकारी तैनात किये गए हैं, जिसका उद्देश्य रोडवेज बस स्टेशन में यात्री सुविधाओं में सुधार करना है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत यात्रियों को गर्मी से राहत देने के लिये प्रत्येक बस अड्डे पर स्वच्छ पेयजल व वाटर कूलर की व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बस स्टेशनों पर साफ-सफाई की व्यवस्था के अलावा महिला-पुरुषों के शौचालयों की नियमित सफाई भी होगी।
- साथ ही बस स्टेशनों को रिपैंट (Repaint) किया जाएगा और यात्रियों को समय-सारिणी एवं किराया तालिका के बारे में सूचित करने वाले नये संकेत भी लगाए जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त बस स्टेशनों पर यार्ड, भवन और कमरों की मरम्मत की जाएगी। यात्री शेड में सीटों की व्यवस्था के साथ ही गर्मी से राहत देने के लिये रोशनी, पंखे/कूलर की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

नीति आयोग की नवोन्वेषी कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला

चर्चा में क्यों ?

25 अप्रैल, 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नीति आयोग द्वारा नवोन्वेषी कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली शामिल हुए।

प्रमुख बिंदु

- प्रथम-सत्र नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. रवि कुमार की अध्यक्षता में हुआ। राज्यों में प्राकृतिक खेती पर हुए प्रथम तकनीकी-सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने भी वर्चुअली अपने विचार रखे।
- प्राकृतिक खेती और नवोन्मेषी कृषि को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 35 ज़िलों के लिये भारत सरकार द्वारा 82.83 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
- मुख्यमंत्री ने 'गाय आधारित प्राकृतिक खेती और नवीन कृषि' पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि यह योजना लगभग 38,670 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी। यह योजना इस साल खरीफ सीजन से शुरू होकर तीन साल के लिये लागू की जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र पारंपरिक रूप से विभिन्न रूपों में प्राकृतिक खेती का अभ्यास कर रहा है। इसे और बढ़ावा देने के लिये, राज्य सरकार ने क्षेत्र के सभी सात ज़िलों के सभी 47 विकास खंडों में 500-1,000 हेक्टेयर के क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। अगले पाँच वर्षों में 175.46 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर लगभग 47,000 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा जाएगा, जिससे 1.17 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश 619.47 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल कर देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य बन गया है।
- प्राकृतिक खेती के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्य के पोषण के लिये उचित पोषण प्रदान करने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य को पूरा करना होगा। इन सभी विविध लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक तरीका गाय आधारित प्राकृतिक खेती है।
- गाय आधारित प्राकृतिक खेती का अर्थ है- कम लागत और विषमुक्त खेती। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की 'गो वंश' पर प्रमुख निर्भरता है, जबकि कृषि का मशीनीकरण किया जा रहा है, कृषि अर्थव्यवस्था में बैलों की उपयोगिता भी महसूस की गई है।
- पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये गंगा नदी के 10 किमी. के दायरे में प्राकृतिक खेती को अपनाने हेतु अभियान शुरू किया गया है और नमामि गंगे के तहत चयनित ज़िलों में गंगा नदी के 10 किमी. के दायरे में बागवानी और कृषि वानिकी को भी प्राकृतिक खेती में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम से दो लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा।
- नमामि गंगे और परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा था, जिसमें 4,784 क्लस्टर के गठन के साथ 75,680 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया था, जिससे 1.75 लाख किसान लाभान्वित हुए।
- परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत जैविक खेती के लिये 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तीन साल की अवधि हेतु प्रदान किये गए, जिसमें 31,000 प्रति हेक्टेयर किसान प्रोत्साहन राशि भी शामिल है।

उत्तर प्रदेश के सभी थानों में स्थापित किये जाएँगे साइबर हेल्पडेस्क

चर्चा में क्यों?

26 अप्रैल, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि गृह विभाग ने साइबर अपराध की जाँच के लिये एक बड़ी कार्य योजना तैयार की है और सभी थानों में साइबर हेल्पडेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रवक्ता ने यह भी बताया कि लखनऊ में एक डिजिटल फोरेंसिक लैब और हर ज़ोन स्तर पर एक साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त साइबर अपराध मुख्यालय में उच्च गुणवत्ता वाला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिये साइबर अपराध मुख्यालय में कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
- साथ ही हर ज़िले में प्रमाणित अपराध रोकथाम विशेषज्ञ (Certified Crime Prevention Specialists – CCPS) नियुक्त किये जाएंगे।
- गौरतलब है कि पिछले पाँच वर्षों में प्रदेश में 18 रेंज-स्तरीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किये गए हैं, वहीं प्रत्येक क्षेत्रीय साइबर अपराध थाने में महिला साइबर अपराध प्रकोष्ठ भी स्थापित किये गए हैं।

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में लॉन्च होगा सामुदायिक रेडियो स्टेशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संस्कृति विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में 'जय घोष' नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इस रेडियो स्टेशन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है।
- संस्कृति विभाग अमृत महोत्सव के अवसर पर राज्य के 75 ज़िलों के समृद्ध इतिहास को दर्शाने वाली 75 पुस्तकों का प्रकाशन के साथ देशभक्ति पर आधारित 75 लघु फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शन भी करेगा।

नोट :

- इसके अतिरिक्त संस्कृति विभाग द्वारा अपनी छह महीने की कार्ययोजना के तहत हर ज़िले में 'एक ज़िला-एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम' आयोजित करने की योजना है।
- साथ ही सरकारी अभिलेखागार, लखनऊ में स्वतंत्रता की गाथा पर आधारित एक गैलरी के निर्माण के साथ संत कबीर, संत रविदास और बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक 'त्रिधारा' राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

चेक डैम्स और तालाबों से बदल रही सूखाग्रस्त बुंदेलखंड की तस्वीर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि नये चेक डैम्स और तालाबों के निर्माण से सिंचाई के लिये पानी की उपलब्धता से क्षेत्र में कृषि उपज में वृद्धि के साथ पशुओं के लिये पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।

प्रमुख बिंदु

- जल शक्ति मंत्रालय के लघु सिंचाई विभाग ने बुंदेलखंड पैकेज के तीसरे चरण के तहत 317 चेक डैम्स का निर्माण और 218 तालाबों के जीर्णोद्धार का काम पूरा कर लिया है। योजना के तहत 328 चेक डैम्स तथा 238 तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
- गौरतलब है कि बुंदेलखंड एक सूखाग्रस्त पठारी क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले तथा मध्य प्रदेश के 8 ज़िले शामिल हैं।
- बुंदेलखंड क्षेत्र में जलाभाव की समस्या को देखते हुए ही केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में दोनों राज्यों (उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश) के मध्य समझौता किया जा चुका है।

वाराणसी में बनेगा उत्तर प्रदेश का अपना 'सिल्क एक्सचेंज'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि जल्द ही वाराणसी में राज्य का 'सिल्क एक्सचेंज' स्थापित होने जा रहा है, जिससे व्यापारियों और साड़ी निर्माताओं को उचित मूल्य पर रेशम की उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु

- 'सिल्क एक्सचेंज' क्षेत्र में रेशम की तस्करी रोकने के साथ ही रेशम व्यापारियों और विनिर्माण इकाइयों के लिये उत्पादन लागत कम करेगा। प्रवक्ता के अनुसार अगले छह महीनों में राज्य सरकार क्षेत्र के बुनकरों को 'सिल्क एक्सचेंज' से जोड़ेगी।
- उत्तर प्रदेश के रीलर्स द्वारा 'सिल्क एक्सचेंज' में बिक्री के लिये लाए गए सभी रेशम लॉट की गुणवत्ता परीक्षण के बाद प्रत्येक रेशम लॉट का न्यूनतम मूल्य राज्य में रेशम के औसत मूल्य और विशेष लॉट की गुणवत्ता के आधार पर तय किया जाएगा। इसके बाद रेशम के लॉट की नीलामी कर एक्सचेंज द्वारा रीलर्स को स्पॉट पेमेंट सुनिश्चित किया जाएगा।
- प्रवक्ता ने यह भी बताया कि राज्य सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना के तहत 'सिल्क एक्सचेंज' के डिजिटाइजेशन पर भी काम करेगी, जिसके माध्यम से बुनकरों, सूत बनाने वाली इकाइयों और 'सिल्क एक्सचेंज' को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, ताकि बुनकरों के तैयार रेशम उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन के लिये एकल मंच की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

नोट :